[Shri Chintamani Panigrahi]

sub-human conditions Forming over 10% of the total strength of 1,60,000 labourers of that textile industry, they are listed as casuals, and are given 12-hours shift, against 8-hour shift under rules. Preference is given to child workers, whose average daily wage is Rs. 5/- to Rs. 7/-. The adult workers get only Rs. 12/- to Rs. 16/- per day.

The workers have no Pave facilities, except a "forced" unpaid weekly holiday, which at times is doubled, depending upon power supply. It is a tragedy that each unit in the city preferred to recruit migrant labour in such a manner that no single ethnic group could have a majority in the establishment.

Unless Central Government intervenes, the poor migrant labourers will continue to suffer. As such, I request the Minister of Labour to intervene in the matter, and protect the poor workers from exploitation, as early as possible.

(vi) Demand for a Separate Postal Division for Yavatmal District, Maharashtra.

SHRI UTTAMRAO PATIL (Yavatmal) : There was a very strong demand from the people of Yavatmal district of Maharashtra for opening a separate postal division. Taking into consideration the absolute necessity and feasibility, I think the DGP&T had approved the proposal some time back. Now the proposal is pending with PMG Bombay. As a matter of fact, the proposal should have materialised, and a separate postal division opened well before the 29th February 1984. But so far, this has not happened.

Therefore, I request hon. Minister for Communications to intervene in the matter, and direct the concerned authorities to open the aforesaid Postal division for Yavatmal district of Maharashtra immediately.

(vii) Financial Assistance to Andhra Pardesh for relief measures in flood affected areas of Nellore and Chittoor Districts.

SHRI PASALA PENCHALAIAH (Tirupathi) : Due to unseasonal heavy rainfall on 13th, 14th, 15th and 16th of February 1984 in Nellore and Chittoor districts of Andhra Pradesh, paddy crop, houses and cattle were affected very badly. Seventyfive per cent of the affected area in Chittoor and Nellore districts is in my Tirupati parliamentary constituency. I toured for five days, and met several farmers, local leaders and officials, and assessed the loss as under :

Nearly 50,000 hectares of paddy ready for harvesting, was severely damaged, and 10,000 hectares of groundnut, chilly and several other commercial crops were damged. The total loss is estimated to be nearly Rs. 50 crores; in addition to loss of cattle, sheep and human lives. Nearly 6,000 thatched houses were also damaged. Further, 300 irrigation tanks were breached, and standing crops were washed away. Nearly 400 village roads were washed away, due to which Rs. 4.56 crores of loss has occurred. Some of the farmers who were affected by the recent unprecedented heavy rains committed suicide, bring unable to bear the heavy loss. The State Government did not take adequate precustionary and timely relief measures.

I, therefor, request the Government to take appropriate action and release financial assistance to Andhra Pradesh, with guidelines for effective implementation of relief measures in flood-effected areas in Nellore and Chittoor districts of Andhra Pradesh.

(viii) Dissatisfaction among employees of Defence Accounts Office at Patna.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : पटना स्थित रक्षा लेखा कार्यालय पूर्वी कमान के मुख्यालय के रूप में स्वतंत्रता

प्राप्ति के पहले से काम करता आ रहा है। इसकी 160 शाखाएं है पहले यह विभाग वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत था। अब अगस्त 1983 से यह रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत है।

सन् 1971 में इस कार्यालय को विभाजित कर शिलांग ले जाने का प्रयत्न किया गया। 19 5 से पटना कार्यालय में हो रहे कार्यों को धीरे धीरे कलकत्ता सिलीगुडी और शिलांग में ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कर्मचारियों द्वारा इन कदमो का विरोध करने पर उन्हे आश्वासन दिया गया कि पटना कार्यालय में हो रहे कार्य एव कर्मचारी यथावत रहेगे।

आश्वासनों के बावजूद मई 1982 मे अचानक पटना कमान के ही अंदर एक दूसरा कार्यालय गोहाटी में खोल दिया गया। कर्मचारियों ने पटना कार्यालय के कामो एवं कर्मचारियों की संख्या में कटौती के मसले को लेकर 50 दिनो तक विरोध आंदोलन चलाया। बिहार विधान मडलों के कुछ सदस्यों, सासदों एवं बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वित्त मत्री को ज्ञापन देकर पटना कार्यालय को कमजोर करने का विरोध किया। वित्त मंत्री ने 27 जुलाई 1982 को आश्वासन भी दिया कि पटना रक्षा लेखा कार्यालय को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। परतु इस आश्वासन के बावजूद सितबर 1983 से पटना कार्यालय के काम और कर्मचारी बाहर भेजे जा रहे है। सरकार से कर्मचारियों की मांग है कि वह जहां चाहे रक्षा लेखा कार्यालय खोले पर पटना मुख्यालय को यथावत रहने दिया जाए।

मेरा रक्षा मत्री से अनुरोध है कि वह वित्त मंत्री के आश्वासन के अनुसार काम कर रहे कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष को दूर करें अन्यथा स्थिति विस्फोटक हो जा सकती है।

(ix) Steps to improove the working of Madhva Pradesh Electric Instrument Ltd.

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड नामक उद्योग जबलपुर के गोसलपुर नामक स्थान पर 20 अप्रैल, 1974 को स्थापित हुआ तथा 20 अप्रैल, 1976 को उत्पादन प्रारंभ हुआ। इस उद्योग में मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य की पूंजी लगी है तथा इस उद्योग का संचालन कर्नाटक राज्य द्वारा भेजे गए शासकीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इस कारखाने में बिजली उत्पादन हेतु आवश्यक ट्रासफारमरों का निर्माण किया जाता है।

यह उद्योग लगातार घाटे में चल रहा है। उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल तथा अतिरिक्त पूंजी जुटा पाने में संचालक असफल रहे है। उत्पादन की गति अत्यंत दयनीय है। इस कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज इस उद्योग की स्थिति यह है कि इसमें शेयर 80 लाख के है परंतु घाटा अनुमानत: 2 करोड़ तक पहुंच गया है।

गोसलपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र में एकमात्र उद्योग है जिसके कारण बड़ी मात्रा में श्रमिक रोजी रोटी पा रहे हैं। यदि यह उद्योग बंद हो गया तो विषम परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। वित्तीय संस्थाएं नया कर्ज देने को तैयार नहीं हैं तथा उत्पादन हेतु